दीवानी विविध

माननीय न्यायमूर्ति एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

जोगिंदर सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाता

1967 की सिविल रिट संख्या 2823

13 फरवरी, 1970।

पंजाब नगर सुधार न्यास अधिनियम (1922 का IV103—) - धारा 5 और भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 14 और 245 - धारा 103 - क्या संविधान के दायरे से बाहर है - राज्य सरकार द्वारा आदेशित एक सुधार ट्रस्ट का विघटन - ऐसे ट्रस्ट के अध्यक्ष को पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार है या नहीं।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की एक सुधार ट्रस्ट का निर्माण या उसका उन्मूलन विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य है जिसके लिए किसी न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। पंजाब नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1922 किसी शहर के सुधार के लिए योजनाओं की तैयारी और निष्पादन से संबंधित है और राज्य सरकार, अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि ट्रस्ट बनाया जाए या जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्णय पर निर्णय ले और यह निदेश दे कि किसी न्यास को समाप्त न किया जाए क्योंकि ऐसा करने पर अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाया जाएगा। किसी न्यास के सृजन, उसे जारी रखने या समाप्त करने के मामले में किसी नागरिक का कोई कानूनी अधिकार शामिल नहीं है और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे ऐसे किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अधिनियम की धारा 103 इस आधार पर संविधान के विपरीत नहीं है कि राज्य सरकार को व्यापक, बेलगाम और निरंकुश शक्तियां दी गई हैं। (पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया है की एक सुधार ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट के विघटन के बावजूद उस कार्यालय में बने रहने के कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वह है केवल राज्य सरकार का नामित व्यक्ति और अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब ट्रस्ट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ट्रस्ट के विघटन की तारीख को समाप्त माना जाएगा। यह भी प्रावधान है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। इसलिए, उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है, यहां तक कि सरकार की चाल। (पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में यह अभिनिर्धारित किया गया है की प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 1967 की अधिसूचना संख्या 6191-सीआई (आई) -67/20106 को रद्द करते हुए सर्टियोररी, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। और प्रतिवादी नंबर 1 को अंबाला शहर सुधार ट्रस्ट को अस्तित्व में माना जाए और इसे समाप्त नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कहा गया है जैसे कि वह उस पद पर बना हुआ है।

याचिकाकर्ता की ओर से जोगिंदर सिंह वासू और वकील इंद्रजीत स्याल पेश हुए।

आर. ए. सैनी, एडवोकेट-जनरल के वकील (हरियाणा), प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

निर्णय।

माननीय न्यायमूर्ति एच. आर. सोढ़ी - यह रिट याचिका अंबाला शहर के प्रैक्टिस करने वाले वकील श्री जोगिंदर सिंह द्वारा दायर की गई है। वर्ष 1962 में, उन्हें पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत तीन साल की अवधि के लिए अंबाला शहर सुधार ट्रस्ट (इसके बाद ट्रस्ट के रूप में संदर्भित) के मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें एक बार के पहले कार्यकाल की समाप्ति पर एक और वर्ष के लिए उसी पद पर फिर से नियुक्त किया गया था और जनवरी, 1966 में, उन्हें 1 फरवरी, 1966 से पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रिट याचिका में एक संदर्भ ज्ञापन संख्या 4066-4CIII-66/13051, दिनांक 181 मई, 1966 को दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अवधि 2 नवंबर, 1965 से तीन साल तय की गई है। इस ज्ञापन की एक प्रति न तो याचिकाकर्ता द्वारा और न ही राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई है। जो भी हो, मेरे सामने यह बात नहीं है कि याचिकाकर्ता को 31 मई, 1966 को ट्रस्ट का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और तीन साल की अवधि 2 नवंबर, 1965 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शुरू होनी थी। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह वेतनभोगी पद था या मानद पद था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वकील होने के नाते याचिकाकर्ता ने अपनी नियुक्ति के नियमों और शर्तों से संबंधित विवरण का खुलासा करने का विकल्प नहीं चुना है।

(2) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब के समग्र राज्य का पुनर्गठन किया गया और हरियाणा राज्य पूर्ववर्ती पुंज± राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। हरियाणा राज्य द्वारा 14 अगस्त, 1967 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 103 के (1) के तहत, हरियाणा के राज्यपाल ने अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ट्रस्ट को भंग कर दिया। यह वह अधिसूचना है जिसे मुख्य रूप से चुनौती दी गई है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आक्षेपित अधिसूचना में, कारण यह दिया गया है कि राज्य सरकार ने ट्रस्ट को भंग करने के लिए समीचीन माना। धारा 103 के तहत:-

"103. (1) जब इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सभी योजनाएं निष्पादित की गई हैं या अब तक निष्पादित की गई हैं ताकि राज्य सरकार की राय में न्यास का निरन्तर अस्तित्व बना रहे, अनावश्यक हो, या जब राज्य सरकार की राय में यह समीचीन हो कि न्यास का

अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि न्यास को ऐसी तारीख से भंग कर दिया जाएगा जो निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की जाए। इस संबंध में ऐसी अधिसूचना और ट्रस्ट को तदनुसार भंग माना जाएगा।

(2) उक्त तिथि से-

(क) सभी संपत्तियां, निधियां और देय राशियां जो क्रमशः न्यास और अध्यक्ष द्वारा निहित या वसूली योग्य हैं, नगरपालिका समिति में निहित होंगी और वसूल की जाएंगी; और

(ख) सभी देनदारियां जो ट्रस्ट के खिलाफ लागू करने योग्य हैं केवल नगरपालिका समिति के खिलाफ लागू करने योग्य होगा; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी ऐसी योजना के निष्पादन को पूरा करने के उद्देश्य से, जिसे न्यास द्वारा पूरी तरह से निष्पादित नहीं किया गया है और खंड (क) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निधियों और देय राशियों की वसूली के उद्देश्य से, इस अधिनियम के अधीन न्यास और अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन नगरपालिका समिति और नगरपालिका समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा क्रमानुसार; और

(घ) नगरपालिका समिति इस अधिनियम के अधीन प्राप्त और व्यय किए गए सभी धनों का अलग-अलग लेखा-जोखा रखेगी, जब तक कि इसके अधीन उठाए गए सभी ऋणों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, और जब तक खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य सभी देयताओं को विधिवत पूरा नहीं किया जाता है।

3. श्री वासू का तर्क यह है कि न्यास को भंग किया जाना प्रामाणिक नहीं था, बल्कि शक्ति का एक रंगीन प्रयोग था, क्योंकि उस समय राज्य सरकार ने संयुक्त दल नामक एक राजनीतिक दल के कुछ प्रस्तावों पर कार्रवाई की थी जो न्यास को समाप्त करना चाहते थे। राज्य ने अपने रिटर्न में इस बात से इनकार किया है कि उसने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कार्रवाई की है और याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के आरोपों के खिलाफ कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया था। वस्तुत, हम जो देखते हैं वह यह है कि राज्य में सभी न्यासों को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता यथोचित रूप से ऐसा नहीं कर सकता है। आग्रह है कि राज्य सरकार किसी बाहरी कार्य से प्रेरित थी। एक विशेष ट्रस्ट को समाप्त करने में विचार ताकि याचिकाकर्ता को कार्यालय से बाहर कर दिया जाए।

4. श्री वासु का अगला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को तीन साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और उस अवधि की समाप्ति से पहले, ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता था या किसी भी दर पर याचिकाकर्ता को उसके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता था। मुझे डर है कि विवाद पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से याचिकाकर्ता ट्रस्ट के विघटन के बावजूद उस कार्यालय में बने रहने

के कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। वह राज्य सरकार का सिर्फ एक नामित व्यक्ति था, जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है, और अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जब ट्रस्ट का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो अध्यक्ष की अवधि ट्रस्ट के विघटन की तारीख को समाप्त मानी जाएगी। निवर्तमान अध्यक्ष या न्यास का कोई सदस्य निसंदेह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है और यह भी प्रावधान है कि उसे राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय एक बार हटाया जा सकता है। कानून का यह प्रावधान कानूनी अधिकार की सीमा निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता को कार्यालय बनाए रखना था। वह उस पद को स्वीकार करने का विकल्प चुनता है जहां उसे राज्य सरकार की दया पर रखा गया था और उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है, यहां तक कि राज्य सरकार की इच्छा पर भी। अधिनियम की धारा 4 एक ट्रस्ट का गठन करती है। तीन सदस्यों को नगरपालिका समिति द्वारा चुना जाना है और अध्यक्ष सहित चार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है। धारा 9 में कहा गया है कि अध्यक्ष को ऐसा वेतन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन, जैसा कि पहले ही कहा गया है, याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है और न ही उसके वकील ऐसा कहने की स्थिति में हैं कि क्या याचिकाकर्ता को कोई वेतन मिल रहा है और राशि क्या थी। किसी व्यक्ति को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को उस नियुक्ति को वापस लेने का अधिकार है जब तक कि इसके विपरीत कोई अनुबंध न हो या कानून का कोई प्रावधान न हो जो ऐसा करने के रास्ते में रोड़ा बन जाए। मुझे ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है जिससे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार के प्रयोग में बाधा उत्पन्न की जा सके ताकि उसे उसके द्वारा की गई नियुक्ति को वापस लेने से रोका जा सके। याचिकाकर्ता वास्तव में यह भी दावा नहीं करता है कि उसने अध्यक्ष के रूप में शामिल होने में राज्य के साथ कोई अनुबंध किया है। यदि कोई अनुबंध था, तो उपचार एक साधारण सिविल न्यायालय में नुकसान के लिए मुकदमे के माध्यम से उसके उल्लंघन के लिए था। श्री वासू का कहना है कि याचिकाकर्ता को पद धारण करने का अधिकार था और इस संबंध में उन्होंने पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारतीय संघ (1) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले कर्मचारी और ट्रस्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति के बीच कोई समानता नहीं है। सिविल पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में भी, राज्य सरकार के लिए पद को समाप्त करना खुला है, लेकिन वर्तमान रिट याचिका के उद्देश्य के लिए उस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है।

5. श्री वासु का अंतिम तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 103 संविधान के दायरे से बाहर है क्योंकि यह ट्रस्ट को समाप्त करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा दुरुपयोग करने में सक्षम व्यापक, निरंकुश और निरंकुश शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि इस प्रकार दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है और बाहरी कारणों से इसका उपयोग किया जा सकता है और इसलिए धारा 103 को असंवैधानिक के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए। मैं संतुष्ट हूं कि विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है। एक ट्रस्ट का निर्माण या उसका उन्मूलन विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य है जिसके लिए किसी न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है।यह अधिनियम किसी शहर के सुधार के लिए योजनाओं की तैयारी और निष्पादन से संबंधित है और राज्य सरकार, अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह तय करने के लिए सबसे

अच्छा न्यायाधीश है कि क्या एक ट्रस्ट बनाया जाए या जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्णय पर निर्णय ले और यह निदेश दे कि किसी न्यास को समाप्त न किया जाए क्योंकि इसके लिए अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाना होगा। किसी न्यास के सृजन, उसे जारी रखने या समाप्त करने के मामले में किसी नागरिक का कोई कानूनी अधिकार शामिल नहीं है और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे ऐसे किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। "योग्यता" का न्यायाधीश अकेले राज्य सरकार है। इस मामले में, जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा है, हम पाते हैं कि कई योजनाएं तैयार की गई थीं और कोई भी निष्पादित नहीं की गई थी। राज्य ने अपनी वापसी में कहा है कि ट्रस्ट के कामकाज के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। केवल यह तथ्य कि योजनाएं बनाई जाती हैं और निष्पादित नहीं की जाती हैं, राज्य सरकार के लिए एक ट्रस्ट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। जब किसी ट्रस्ट को समाप्त कर दिया जाता है, तो ट्रस्ट और अध्यक्ष के कार्यों को नगरपालिका समिति और उसके अध्यक्ष द्वारा संभाला जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 103 (2) (सी) में परिकल्पना की गई है। इस प्रकार यह निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है कि क्या किसी शहर के विकास को केवल नगरपालिका समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए अथवा एक सुधार न्यास का सृजन किया जाना चाहिए।

6. पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका में कोई दम नहीं है जिसे खारिज कर दिया गया है। मामले की अजीब परिस्थितियों में , मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।